विजय शर्मा
उप मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ शासन
गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
क्रमांक 1899\पं.ग्रा.वि.\2026
रायपुर, दिनांक 09-06-2026

प्रति,

मानानीय विष्णुदेव साय जी,
मुख्यमंत्री
छ.ग. शासन

महोदय,

विगत ढाई वर्षो से मैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के भार साधक मंत्री के रूप में कार्यरत हूं। इस अवधि में सभी के सहयोग से प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के कार्य में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त हुई है।

महोदय, विगत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के लिए राशि का आबंटन नहीं किया था। जिससे लाखों गरीब पक्के आवास से वंचित रह गए थे। तात्कालीन सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैय्ये से क्षुब्ध होकर उस सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री ने विभाग को त्याग दिया था।

तब **"मोर आवास–मोर अधिकार"** एक जन आंदोलन बना था। गांव से राजधानी रायपुर तक जन सैलाब उमड़ा था। इस आंधी में पूर्ववर्ती सरकार उखड़ गई थी। इसी आंदोलन में हितग्राहियों के चरण पखार कर जनता से वादा किया गया था कि, यदि भाजपा की सरकार बनती है तो सरकार की "पहली कैबिनेट का पहला प्रस्ताव" गरीबों को पक्का आवास देने का संकल्प होगा। छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से भाजपा की सरकार बनी और यह वादा पूरा भी किया गया ।

14 दिसंबर 2023 के कैबिनेट के प्रथम बैठक में–

- सभी अपूर्ण – 2,46,215 आवास
- 2011 के स्थायी प्रतीक्षा सूची के – 6,99,438 सभी शेष आवास
- आवास प्लस की सम्पूर्ण सूची – 8,19,999
- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण आवास न्याय योजना) के – 47,090 संपूर्ण आवास

कुल–18,12,742 (अठ्ठारह लाख बारह हजार सात सौ बयालीस) आवास को पूर्ण करने का संकल्प पारित किया गया था। साथ ही पीएम जनमन के 33,601 तथा नक्सल क्षेत्र हेतु विशेष परियोजना अंतर्गत 15000 आवास और भी बनाये जा रहे है।

पूर्व मंत्री श्री टी.एस.सिंहदेव ने अपने त्यागपत्र में उल्लेख किया था कि उनकी सरकार ने उनके अनेक प्रयासों के बाद भी गरीबों के पक्के आवास हेतु राशि उपलब्ध नहीं

क्रमशः-2

विजय शर्मा
उप मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ शासन
गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

क्रमांक .....

रायपुर, दिनांक .....

करवाई थी परंतु हमारी सरकार ने 26908 करोड़ (छब्बीस हजार नौ सौ आठ करोड़) की राशि बजट के माध्यम से प्रदान कर प्रदेश के गरीबों के पक्के आवास का सपना साकार कर दिया।

"मोर आवास–मोर अधिकार" अभियान आगे बढ़ा और आपकी सरकार गठन के उपरांत ऐतिहासिक सफलता हासिल करते हुए समुचे प्रदेश में ढाई वर्षो में 10.60 लाख (दस लाख साठ हजार) से अधिक आवास पूर्ण कर लिये गए।

इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ ने –

देश में सर्वाधिक –अप्रेल से अक्टूबर 2025 तक प्रतिदिन लगभग 2000 आवास पूर्ण किए।

देश में सर्वाधिक –आज भी प्रतिदिन 1600 से अधिक आवास पूर्ण किए जा रहे हैं।

देश में सर्वाधिक –वर्ष 2025–26 में छत्तीसगढ़ प्रदेश ने 6 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए।

महोदय हमने न केवल अपने वादे पूरे किये अपितु विगत सरकार के मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण आवास न्याय योजना) के हितग्रहियों की बकाया राशि भी जारी की।

महिला स्वसहायता समूहो ने आगे बढ़कर डीलर दीदी, रानी मिस्त्री बनकर इस विशाल काम को थाम लिया। हजारों दीदीयाँ इससे लखपति दीदी बनी। अटल डिजिटल सुविधा केंद्र ने छोटे–छोटे लेन–देन को गांव में ही सुलभ बनाया तथा आपके आव्हान और जन जागरण से समस्याएं न्यूनतम स्तर पर पहुंच गईं।

मान्यवर, पुनः पूरे विभाग ने उत्साह के साथ **"आवास प्लस 2.0–2024"** के अंतर्गत ऐसे गरीब जिनके आवास कच्चे हैं उनका सर्वे किया है और प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है।

मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, आपका तथा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहन जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों की प्रेरणा से आज प्रदेश के लाखों गरीबों का पक्का आवास बन सका है।

धन्यवाद

आपका

(विजय शर्मा) 9.6.26

कार्यालय : कक्ष क्रमांक एम 4–1, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) दूरभाष नं. 0771–2510904, 2221104
निवास : सी–3 सिविल लाईन, रायपुर (छ.ग.) दूरभाष नं. 0771–2445561, 91092–55611, ई–मेल : cghm.72@gmail.com